>

Title: Issue regarding misutilization of MNREGA Fund.

**श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़):** माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार की एक अति महत्वपूर्ण योजना मनरेगा है, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा अरबों रुपयों का बजट प्रत्येक राज्य को आबंटित किया जाता है तथा जिन राज्यों में मनरेगा योजना का सुचारू संचालन हुआ है, वहां के निवासियों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ है। जिसका ज्वलंत उदाहरण मेरे संसदीय क्षेत्र माँ जालपा की नगरी राजगढ़ का है, जहां के ग्रामीण लोग पूर्व में एक वर्ष में लगभग आठ महीने राजस्थान के कोटा तथा अन्य जिलों में अपने परिवार के साथ मजदूरी करने जाते थे जिससे उनका साल भर के लिए जीवन यापन करने हेतु मात्र राशन पानी की ही व्यवस्था हो पाती थी। लेकिन आज मनरेगा ने मेढ़ बंधान एवं कूप निर्माण, भूमि सुधार जैसी योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया है।

महोदय, इसमें एक बहुत बड़ी विसंगति है जो मध्यप्रदेश राज्य में आ रही है। जहां राज्य शासन द्वारा समय पर एमआईएस न करने के कारण तकनीकी कारणों से केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त राशि जारी नहीं की जा सकती है। प्रदेश सरकार की इस गलती का खामियाजा मनरेगा के मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। इस संबंध में मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में इस महत्वपूर्ण जीवनदायिनी योजना की समीक्षा की जाए तथा जो राज्य समय पर एमआईएस न करे अथवा मनरेगा की राशि किसी अन्य योजना में उपयोग कर ले, जैसा कि मध्य प्रदेश राज्य करता आ रहा है। ऐसे राज्यों में जिस प्रकार भारत सरकार के रेलवे, हवाई यातायात और दूरदर्शन जैसे विभाग, बिना राज्य सरकार के हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं। उसी प्रकार इस मनरेगा योजना के समुचित संचालन हेतु भी केंद्र सरकार का अमला, ऐसे राज्यों में स्थापित किया जाना चाहिए जिससे इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ सीधे हमारे देश के मजदूर वर्ग को ही मिले और राज्य सरकारें केंद्र शासन की ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं का दुरुपयोग न कर पाएं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।